



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222169
CG-DL-E-30092020-222169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942

No. 279]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

मामला सं. एडी (ओआई) – 29/2020

विषय : चीन जन.गण. से “हाइड्रोफ्ल्यूओरोकार्बन (एच एफ सी) ब्लैंड्स” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 6/34/2020 – डी जी टी आर.—1. मै. एस आर एफ लिमि. (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये “हाइड्रोफ्ल्यूओरोकार्बन (एच एफ सी) ब्लैंड्स” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है।

- आवेदन ने चीन जन. गण. से एच एफ सी ब्लैंड्स के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति का आरोप लगाया है और यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देश से एच एफ सी ब्लैंड्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाये।

विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी)

3. विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्ल्यूओरोकार्बन (एच एफ सी) ब्लैंड्स है। 407 और 410 को छोड़कर सभी ब्लैंड्स को बाहर रखा गया है"।
4. एच एफ सी ब्लैंड्स आर-407 और आर-410 रंग रहित, गंध रहित गैस हैं, जिनमें केवल हाइड्रोजन, फ्ल्यूओरिन और कार्बन होते हैं। उन्हें सी एफ सी और एच सी एफ सी जैसे आर-22 जो ओजोन लेयर को खाली करता है और जिसका व्यापक रूप से उपयोग रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन के लिए किया जाता है, ओजोन अनुकूल प्रतिस्थापन के रूप में विकसित किया गया है। ये दो प्रमुख अंतिम उपयोग आवासीय वातानुकूलन और हीट पंप व्यापारिक वातानुकूलन, व्यापारिक रेफ्रिजरेशन, दुलाई रेफ्रिजरेशन और प्रॉसेस रेफ्रिजरेशन जैसे खाद्य प्रसंस्करण और रासायनिक निर्माण हैं। आर-407 का मुख्य रूप से उपयोग आवासीय एयर कंडीशनरों, हल्के व्यापारिक एयर कंडीशनरों और मध्यम तापक्रम के व्यापारिक रेफ्रिजरेशन प्रणाली में उपयोग किया जाता है। आर-410 के प्रमुख अंतिम उपयोग में आवासीय और व्यापारिक वातानुकूलन प्रणाली, चीलर्स और हीट पंप शामिल हैं।
5. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क उपशीर्ष संख्या 38247800 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 38 के तहत किया जाता है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यात किये गये और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं का आयात संबद्ध देश से किया जाता है और वे वस्तुओं के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। इसके अलावा आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी रूप से और व्यापारिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से इन्हें नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य भारत में आवेदक द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात किये जा रहे संबद्ध वस्तुओं का "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

क घरेलू उद्योग और स्थिति

7. यह आवेदन मै. एस आर एफ लिमि. द्वारा दायर किया गया है। गुजरात फ्लूरोकेमिकल लिमि. (जी एफ एल) जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र अन्य घरेलू उत्पादक है, को पत्र भेजा गया था। कंपनी ने इस आवेदन का समर्थन करते हुए और अपने उत्पादन के बारे में सूचना उपलब्ध कराते हुए उत्तर दिया था। जी एफ एल ने यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है न ही उनका संबंध संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में पी यू सी के किसी आयातक से है। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, आवेदक का भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।
8. उपर्युक्त को देखते हुए और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के संबंध में पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

9. प्राधिकारी ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के संदर्भ में किया जाना चाहिए। आवेदक ने इस नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(2) का उदाहरण दिया है और यह उल्लेख किया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए निदेश दिया जाना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां इस नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(3) के संदर्भ में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में प्रचलित है। आवेदक ने यह दावा किया है

कि चीन के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। विचाराधीन उत्पाद की कीमतों और संरचित मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले उपयुक्त तीसरे देश में अथवा इस प्रकार के तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमतों को न तो आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया है और न ही यह सूचना किसी भी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ के लिए जोड़ने के बाद विधिवत समायोजित भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत

10. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश के लिए संबद्ध वस्तुओं के वास्ते निर्यात कीमत की गणना की है। कीमत संबंधी समायोजन समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा खर्च, पोर्ट खर्च, बैंक शुल्क और मूल्यवर्धित कर के लिए किया गया है।

पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से पी यू सी के संबंध में बहुत अधिक है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत हासकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि इसके कार्य निष्पादन पर जांच की अवधि के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग और बाजार हिस्से में गिरावट, लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक लाभ, (आर ओ सी ई) और हानि हुई है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा इसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के संबंध में किसी कथित पाटन के होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक (12 महीने) है। क्षति की जांच की अवधि में 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017; 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल होंगी।

प्रक्रिया

16. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए पालन किया जाएगा।

ख सूचना प्रस्तुत करना

17. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्र ई-मेल पते adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir14-dgtr@gov.in तथा jd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
18. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित रूप में अथवा तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित रूप में और तरीके से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
21. इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबद्ध में किसी अद्धधित सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की सरकारी वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित रूप से नजर रखें।

समय सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए ताकि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना के प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपर्युक्त ई-मेल पते पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। हालांकि, यह नोट किया जाये कि उक्त उप-नियम की व्याख्या के संबंध में, सूचना और अन्य दस्तावेजों को मंगाने वाले नोटिस के संबंध में यह माना जायेगा कि वह उस तिथि से एक सप्ताह पहले प्राप्त हो गया है जिस तिथि को इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश से उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा गया था अथवा संप्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना पूरी नहीं हो तब प्राधिकारी इस नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को रिकार्ड कर सकते हैं।
23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्टों/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे पृथक रूप से गोपनीय और अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करें।
26. “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में स्पष्ट से चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्ह के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
27. गोपनीय पाठ में वे सभी सूचना निहित होंगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य प्रकार की सूचना हैं जो इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति गोपनीय के रूप में दावा करते हैं। उस सूचना के लिए, जिसके संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

28. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा कवर किया (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सारांश किए जाने के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति हो। अगोपनीय सारांश विस्तृत ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्योंकि इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।
29. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला व्यक्ति इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
30. उसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
31. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने के तौर तरीकों का निर्धारण किया जा रहा है।

असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

Case No. AD (OI)-29/2020

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Hydrofluorocarbon (HFC) Blends” from China PR.

F. No. 6/34/2020-DGTR.—M/s. SRF Limited (hereinafter also referred to as “Applicant”) has filed an application seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Hydrofluorocarbon (HFC) Blends”, originating in or exported from China PR (also referred to as “subject country”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”).

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports of HFC Blends from China PR and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the HFC Blends from subject country.

Product under Consideration (PUC)

3. The product under consideration is “Hydrofluorocarbon (HFC) Blends. All blends other than 407 and 410 are excluded”.
4. HFC blends R-407 and R-410 are colourless, odourless gases containing only hydrogen, fluorine, and carbon. They were developed as ozone-friendly replacements for CFCs and HCFCs, such as R-22, which deplete the ozone layer and are extensively used for refrigeration and air conditioning. These two major end uses are residential air conditioning and heat pumps, commercial air conditioning, commercial refrigeration, transportation refrigeration, and process refrigeration e.g., food processing and chemical manufacturing. R-407 is mainly used in residential air conditioners, light commercial air conditioners and medium temperature commercial refrigeration system. The main end use of R-410 includes residential and commercial air conditioning system, chillers and heat pumps.
5. The product under consideration is classified under chapter 38 of the Customs Tariff Act under customs sub-heading no. 38247800. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

6. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

A Domestic Industry and Standing

7. The Application has been filed by M/s. SRF Limited. A communication was sent to Gujarat Fluorochemicals Ltd. (GFL) – the only other domestic producer of the product under consideration in India. The company had responded, by supporting the application and providing information about their production. GFL has also stated that they have imported the product under consideration from China PR during the period of investigation. The Applicant has claimed that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. Considering the information on record, the Applicant accounts for a major proportion of the Indian production.
8. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Normal Value of China PR

9. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicant has claimed that for China, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant nor is this information available with the Authority from any public source. The normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

Export Price

10. The Authority has computed export price for subject goods for the subject country based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and VAT.

Dumping Margin

11. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level, and is significant in respect of the PUC from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from subject country is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

12. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in the POI in absolute terms, price undercutting, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted during the POI leading to decline in production, sales, capacity utilization and market share, negative return on capital employed (ROCE) and losses. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Country

14. The subject country for this investigation is China PR.

Period of Investigation

15. The period of investigation for the present investigation is 1st April, 2019 – 31st March, 2020 (12 months). The injury investigation period will cover the periods 1st April, 2016- 31st March, 2017; 1st April, 2017- 31st March, 2018, 1st April, 2018- 31st March, 2019 and the period of investigation.

Procedure

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

B Submission of Information

17. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dirl4-dgtr@gov.in and jd13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
18. The known producers/exporters in the subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
21. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
26. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

32. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

33. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority